सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 167 | जौनपुर, बुधवार, 13 मार्च 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पीएम मोदी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी को बधाई दी

नयी दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नायब सिंह सैनी को बधाई दी और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नायब सिंह सैनी को बधाई। मैं उन्हें और उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर बाद भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सैनी (54) के साथ ही कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जय प्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली।

महिला सशक्तिकरण में कलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका – जोशी

नयी दिल्ली, एजेंसी। कला सोपान और ललित कला संस्थान बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय ,झांसी के संयुक्त तत्वावधान में वामिका द्वितीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन आर्टिजन आर्ट गैलरी , नई दिल्ली में किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ,नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि कलाएं महिला सशक्तिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। डॉ. जोशी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कला प्रदर्शनी में महिलाओं के विविध रूपों को प्रदर्शित किया गया है। समारोह में रंगकर्मी और लेखिका श्रीमती मालविका जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। समारोह के विशिष्ट अतिथि हिन्दी सलाहकार समिति नीति आयोग के सदस्य मनीष कुमार शुक्ल ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। यह महिलाओं को सोचने के लिए विषय देने के साथ ही कार्यात्मक विधि से भी सशक्त करने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मालविका जोशी ने कहा कि बंधन को तोड़कर निकलना ही होगा। कई बार यह हो सकता है कि बंधन को तोड़ने में हमारे पंख भी उखड़ जाएं लेकिन नए पंख आयेंगे और फिर से उड़ान भरेंगे। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।प्रदर्शनी के सह संयोजक गजेन्द्र सिंह ने बताया कि इस कला प्रदर्शनी में 40 से अधिक कलाकारों की 60 से अधिक कला कृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

सीएए की अधिसूचना जारी करने का केंद्र सरकार का निर्णय देश विरोधी - मुख्यमंत्री केजरीवाल

नयी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित करने का नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार का कदम देश विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सीएए लागू करना भाजपा की ''ओछी राजनीति'' है , जिसका मकसद पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को भारत में अपना वोट बैंक बनाना है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)–2019 को लागू करने की घोषणा की। इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर–मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने

का रास्ता साफ हो गया है। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर–मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। केजरीवाल ने एक्स पर कहा, ''10 साल देश पर राज करने के बाद चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आयी है। ऐसे वक्त में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाये हैं।'' आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि भाजपा कह रही है कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, ''इसका मतलब वे पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या भाजपा उनको रोजगार देगी? क्या भाजपा उनके लिए घर बनाएगी?'' केजरीवाल ने कहा कि खासकर असम और पूरे पूर्वोत्तर के लोग सीएए का सख्त विरोध करते हैं।

ममता की दो टूक– मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी

कोलकाता, एजेसी। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन पर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर अशांति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि कल की घोषणा एक लूडो चाल है। बंगाल के हाबरा में एक प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए तृणमूल प्रमुख ने नागरिकता अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें कानून की वैधता पर संदेह है। कोई स्पष्टता नहीं है। यह एक भ्रामक अभियान है। भाजपा नेता कहते हैं कि सीएए आपको अधिकार देता है। लेकिन जैसे ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, आप अवैध प्रवासी बन जाते हैं और आप अपने अधिकार खो देंगे। मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने कल सीएए लागू किया, मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था।

आदिवासी संकल्प से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे – खरगे

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी संकल्प की गारंटी के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों तथा उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आदिवासियों के लिए छह सूत्री संकल्प की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि

मोदी सरकार में वन सरंक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वन क्षेत्र को मित्र पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। खरगे का कहना था, हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसे कानून के तहत करेंगे। खरगे ने कहा, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी, जिनसे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगे के अनुसार, कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां एसटी सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके।

पीएम मोदी ने जो कहा, वो किया - अमित शाह

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रय गृहमंत्री अमित शाह ने यहां सोमवार को 383 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली के 41 गांवों में पाइप्ड नैचुरल गैस सुविधा और 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो किया और वादों को धरातल पर उतारा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन से गैस पहुंचने की शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 178 गांवों के विभिन्न विकास कार्यों की शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और जीवनस्तर को सुधारने के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस पैसे का कोई उपयोग नहीं होता था। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो किया और वादों को धरातल पर उतारने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 13 करोड़ माताओं को गैस सिलिंडर दिए, 1 करोड़

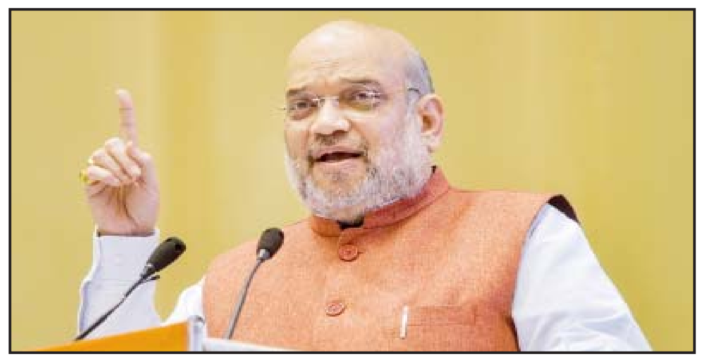

लोगों के घर में पाइप्ड गैस पहुंचाई, 14 करोड़ लोगों के घरों में नल से जल पहुंचाए, 14 करोड़ शौचालय बनाए, 3 करोड़ से अधिक घर बनाए और 60 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। मोदी जी ने लद्दाख से लक्षद्वीप, कामाख्या से द्वारका, किसान से विज्ञान, नई शिक्षा नीति से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सौर ऊर्जा से पीएनजी तक भारत के नागरिकों का हर सपना पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो या सीएए लाना हो, नरेंद्र मोदी ने हर वादा पूरा कर पूरे देश में नए उत्साह, आशा और उमंग का वातावरण बनाया है। इसी कारण आज पूरा देश नए विश्वास के साथ 2047 में देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, देश में आए इस परिवर्तन की कड़ी में जहां पहले एनर्जी पावर्टी थी, उसकी जगह एनर्जी सिक्योरिटी लाने का काम भी मोदी जी ने किया है। सीएनजी बसों, मेट्रो रेल और नई ट्रेन की सेवाओंके माध्यम से नागरिकों का आवागमन भी बहुत सरल बनाने का काम मोदी जी ने किया। इसके साथ ही पीएम–सूर्यघर योजना से गरीब के घर पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाकर उसे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिले, ऐसी व्यवस्था भी मोदी जी ने की है।

सीएम योगी ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा, 2.12 करोड़ परिवारों को मिलने लगा शुद्ध पेयजल

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और अफसरों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हर घर नल–हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज 2 करोड़ 12 लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। हर घर नल से जल पहुंचाने की यह योजना ईज ऑफ लिविंग के संकल्प को पूरा होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बड़े बदलाव का परिचायक है। यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है। यह दोनों ही क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकता में है। अतिशीघ्र विंध्य–बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल की सुविधा होगी। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मीरजापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य–बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का कार्य आखिरी चरण में प्रवेश कर गया है। अवशेष कार्यों को तेजी के साथ पूरा कराया जाए। शुद्ध पेयजल केवल प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि अनेक बीमारियों से सुरक्षित भी रखता है। हमें जल के महत्व को समझना होगा। गांव–गांव में लोगों को समझाना होगा।

हम राष्ट्र निर्माण के लिए विकास कार्य करते हैं, न कि चुनाव जीतने के लिए

अहमदाबाद, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 10 नयी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के साथ 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, ''कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि (चुनाव जीतकर) सरकार

बनाने के लिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह कष्ट न सहना पड़े जो उनकी पिछली पीढ़ियों को झेलना पड़ा। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष में उनकी सरकार ने रेलवे के विकास पर पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक राशि खर्च की है। मोदी ने कहा, ''वर्ष 2024 के केवल दो महीनों में, हमने 11 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

बिना एनआरसी के आवेदन पर किसी को भी नागरिकता मिली तो दे दूंगा इस्तीफा – सीएम सरमा

गुवाहटी, एजेसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बिना एनआरसी के

आवेदन पर नागरिकता मिलती है तो वह इस्तीफा दे देंगे। उनका यह बयान सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को लागू करने पर असम में विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन के बाद आई है। असम के सीएम ने कहा, ष्मैं असम का बेटा हूं और अगर एक भी व्यक्ति जिसने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सीएए लागू होने के बाद लाखों की संख्या में लोग राज्य में प्रवेश किए थे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए को लेकर कुछ भी नया नहीं है अब पोर्टल पर आवेदन का समय आ गया है।ष उन्होंने कहा, ष्अब पोर्टल पर डेटा बताएगा। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि कानून का विरोध करने वालों के लिए यह दावें सही है या नहीं।

सीएए का समर्थन नहीं करने वालों को अदालत जाने का सुझाव

सीएम सरमा ने आगे कहा, सीएए का समर्थन करने वाले भी असम में है और जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे भी यहां है। जो भी सीएए का विरोध कर रहे हैं।

पिछले चार साल के तनाव से ना भारत को कुछ हासिल हुआ, न ही चीन को - जयशंकर

नयी दिल्ली, एजेंसी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगभग चार साल से जारी सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि इस अवधि के दौरान ''तनाव'' से दोनों देशों में से ''किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ।'' जयशंकर ने कहा कि भारत ''निष्पक्ष और उचित समाधान'' खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह ऐसा समाधान होना चाहिए, जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने सोमवार शाम को एक कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान कहा कि भारत ने ''पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का

मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए।'' हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा से लौटे जयशंकर ने नयी दिल्ली में 'एक्सप्रेस अड्डा' के दौरान कूटनीति की बदलती प्रकृति से लेकर बदल रही वैश्विक व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बाद में, उन्होंने राजनयिकों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, पत्रकारों और विदेश नीति के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के एक वर्ग के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब उनसे सवाल किए गए कि सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए ''चीनी पक्ष ने अतीत में किन प्रस्तावों की पेशकश की और क्या कभी ऐसी स्थिति बनी जब उन्हें ऐसा लगा कि इस मुद्दे को वास्तव में सुलझाया जा सकता है, तो मंत्री ने कहा, ''सीमा संबंधी विवादों को लेकर वार्ता कर रहे हर देश को यह मानना होता है कि इसका कोई समाधान अवश्य होगा।'' यह पूछे जाने पर कि यदि वर्तमान सरकार को ''(संसद में) और सीट मिलती है तो क्या वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अधिक सशक्त हो जाएगी'',केंद्रीय मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ''मेरे लिए, भारत की जमीन और सीमा समाधान की निष्पक्षता का सीट की संख्या से कोई लेना–देना नहीं है...या तो कोई समझौता अच्छा होता है।

संपादकीय

जल संकट का स्वरूप आने वाला

आपका और मेरा बड़ा शहर बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है. हो सकता है कि बेंगलुरु की समस्या आज इंदौर और राजकोट की तुलना में बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर आप जिस धरती पर हम रहते हैं, उसके नीचे देखें तो समस्याएं संभावित रूप से हर बड़े शहर के लिए मौजूद हैं। हमारे सामने आने वाली सभी समस्याओं में से पीने योग्य पानी की समस्या सबसे कठिन है। बेंगलुरु अचानक गलत कारणों से सुर्खियों में है। कल से शुरू होने वाली गर्मी के महीनों के दौरान पीने योग्य पानी की भारी कमी है। अचानक, हमारे बोर–वेल पर्याप्त बारिश के बिना सूख रहे हैं। भूजल एक घृणित और मायावी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है, जिस तक पहुंचना अधिक कठिन हो गया है। जहां बोर–वेल के चलन के शुरुआती दिनों में पानी 80–100 फीट की गहराई पर पहुंचता था, वहीं आज का जल स्तर 1,600 फीट पर भी अधिक से अधिक अस्पष्ट होता जा रहा है। ।कअमतजपेमउमदज नदी के पानी का प्राथमिक स्रोत, जो नहरों और जलाशयों के नेटवर्क के माध्यम से शहर को पोषण देता है, तनाव में है। शहर के नए क्षेत्रों में कावेरी या अरकावथी जल तक पहुंच नहीं है, और एक पूरा नया शहर बोर–वेल नेटवर्क की मौसमी खोखली नींव पर बनाया गया है जिसे नियंत्रित करना और भरना मुश्किल हो रहा है। और यह एक ऊंचा शहर है – फ्लैटों और अपार्टमेंटों से भरा शहर जो बेंगलुरु की ऊंचे कद के शहर की नई छवि को परिभाषित करता है। हालाँकि, शहर सूखा चल रहा है। कम से कम कुछ महीनों के लिए. बेंगलुरु में पानी की यह गंभीर समस्या फिलहाल शहर की है। यह किसी अन्य बड़ी आबादी वाले बड़े शहर का भी हो सकता है. अगर मुझे यह पता लगाना शुरू करना है कि शहर आम तौर पर अपनी पानी की जरूरतों का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो उनमें से सबसे अच्छे के पास पीने के पानी का एक स्रोत है जो नदियों और झरनों से आता है। जहां धारा समाप्त होती है, वहां शहर की योजनाबद्ध अप–स्ट्रीम जल आपूर्ति प्रणाली शुरू होती है जो भंडारण टैंकों में आपूर्ति का एक चौनल स्थापित करती है जो पानी को अंतिम घर तक आवश्यकता के अनुसार पुनः प्रवाहित करती है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) शहर के लिए इस प्रणाली का प्रबंधन करता है। मुझसे यह मत पूछो कि ष्जल आपूर्तिष और ष्सीवरेजष एक साथ क्यों चलते हैं। जहां शहर के लिए कावेरी जल की सीधी आपूर्ति संभव नहीं है, नए शहर के बिल्डरों ने भूजल भंडार का दोहन किया है जो अच्छे मानसून से बार–बार भर जाता है। नए क्षेत्रों में बने अपार्टमेंट परिसरों ने उन क्षेत्रों के नीचे श्आसानी से पानीश पाने के लिए बोर–वेल का उपयोग किया है, जहां ये अपार्टमेंट मौजूद हैं। और फिर आम तौर पर अनियोजित शहर में आवासों की अगली श्रेणी आती है। यह वर्ग पानी के मामले में सबसे अधिक गरीब है। इसमें सीधे कावेरी का पानी नहीं है, और न ही इसे बोर–वेल संभावना क्षेत्र में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। यह श्रेणी पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर करती है जो मांग के अनुसार दैनिक या वैकल्पिक दिन के आधार पर पानी लाते हैं। तो आपकी समस्या क्या है, बेंगलुरु? यह शहर आज 142,00,000 लोगों का घर है और उन्हें पानी की दैनिक आवश्यकता है। पीने के लिए पानी, खाना पकाने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, हमारी कारों को धोने के लिए पानी, और बालकनी और विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के निजी उद्यानों में हमारे गमले में लगे पौधों को पानी देने के लिए पानी। मैं पानी के लिए कॉर्पोरेट आवश्यकता के क्षेत्र में कदम भी नहीं रख रहा हूं, और पानी की आवश्यकता आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें बेंगलुरु के विशाल गोल्फ कोर्स भी शामिल हैं। हमें पानी चाहिए. हमें पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान पानी की कमी जो शहर को प्रभावित कर रही है वह अस्थायी है। जिसने हमें इस गर्मी में काट लिया है। मुझे बताया गया है कि यह हमें हर गर्मियों में 2–3 महीने तक काटता रहेगा। क्या हमने इसे आते नहीं देखा? स्पष्ट रूप से नहीं। भले ही हमने इसे आते हुए देखा हो, योजना चक्र में एक अंतराल है जिसके कारण यह पारित हुआ है। कावेरी चरण 5 परियोजना की प्रगति अपेक्षा से धीमी रही है। यह परियोजना मई 2024 से शुरू होने वाले कुछ समय के लिए शहर की जरूरतों का ख्याल रखने का वादा करती है। हमें बताया गया है कि यह अगले कई वर्षों तक हमारे पानी के संकट का ख्याल रख सकती है। उसके बाद, क्या? पूरी तरह से अव्यवस्थित मौसम के माहौल में, जो हमारी गर्मी, सर्दी और मानसून के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, हमारे बड़े शहर पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होने जा रहे हैं। बारिश से हमारे बोर–वेल भर जाएंगे और हम वह सब कुछ कर पाएंगे जो हम पानी की परवाह किए बिना खुशी–खुशी करते हैं। हम बड़े शहर में उत्तरोत्तर वर्षा पर निर्भर लोग बनते जा रहे हैं। चूँकि बेंगलुरु इसकी कमी से जूझ रहा है, क्या मैं समस्या का हिस्सा बनना चाहता हूँ या समाधान का? आइए मैं बाद वाले का हिस्सा बनने का प्रयास करूं। यदि कोई एक समाधान है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं, तो वह उतना ही सरल या जटिल है जितना कि एकत्रीकरण और पृथक्करण शब्द हैं। बड़े शहरों को अपने स्थानों और अपनी आवश्यकताओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक बड़ा शहर अपनी सारी आबादी का भार अनंत काल तक नहीं सह सकता। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु आज एक चुंबक शहर है। देश और दुनिया भर से लोग इस शहर में आना चाहते हैं।

सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून

ललित

संसद में 11 दिसंबर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अर्थात सीएए पारित होने के लगभग चार वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा चुनाव से पूर्व देश भर में लागू करके न केवल अपने राजनीतिक आलोचकों को अचंभित किया है, बल्कि देश अपने लोगों की न्यायपूर्ण नागरिकता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा में बढ़ चला है। यह कानून भारत की नागरिकता को संतुलित, औचित्यपूर्ण एवं समतामूलक बनाने की दिशा में साहसिक कदम है। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मुस्लिमों को अब भारत में सहजता से नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों को सहजता से नागरिकता हासिल हो जाएगी। कानून के तहत पात्र लोग नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौर करने की बात है कि पिछले दिनों से विपक्षी दलों के अनेक नेता सीएए को लागू करने का विरोध करते हुए एक वर्ग–विशेष के लोगों को अपने पक्ष में करने की कुचेष्ठा कर रहे हैं। जबकि भाजपा सरकार एवं उससे जुड़े शीर्ष नेतृत्व इसे लागू होने के संकेत दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आम चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा और जो कहा, उसे कर दिखाया है। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले सीएए को लागू कर सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है। अब इसे लागू करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एक सार्थक पहल का सूत्रपात किया है। सीएए पारित हो गया था और इस कानून को अधिसूचित भी कर दिया गया था, पर इसके लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले देश में नागरिकता नियम तय नहीं हुए थे। कानून बन जाने के बाद नियम तय करना जरूरी होता है और नियम तय करने के लिए सरकार लगातार समय ले रही थी। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही थी। बहरहाल, नियम न तय होने से आगे नई लोकसभा में तकनीकी परेशानियां आ सकती थीं, अतः केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को अंजाम देकर एक तरह से अपना ही अधूरा काम पूरा किया है, एक साहसिक एवं समयोचित कदम उठाया है। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बंगलादेश से आये हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों के लिये एक नये सूरज का उदय है। आगामी चुनाव एक तरह से सीएए पर जनमत संग्रह जैसा होगा। यहां यह याद करने की बात है कि सीएए लागू करने का वादा पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा था और इससे भाजपा को चुनाव में बहुत फायदा भी हुआ था। सीएए के सन्दर्भ में राजनीति से अलग होकर सोचना ज्यादा जरूरी है। जो मजबूर लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देश के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। भूलना नहीं चाहिए, नागरिकता का तार्किक व मानवीय दृष्टिकोण इस देश की 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संस्कृति का अंग है। सीएए के कारण भले ही तथाकथित अराष्ट्रवादी ताकतें एवं विपक्षी दल हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना सकते हैं, लेकिन यह कानून एक आदर्श नागरिकता कानून है, लम्बे समय से इस कानून की जरूरत को महसूस करते हुए अनेक नागरिक घुटन एवं असंतुलित नागरिकता कानून के दंश को भोग रहे थे। व्यक्ति जिस समाज में जीता है, उसकी व्यवस्थाओं, नीतियों और परम्पराओं में जब घुटन का अनुभव करता है तो वह किसी नए मार्ग का अनुसरण करता है। आज आजादी के बाद की राजनीतिक विसंगतियों से पनपी ऐसी ही घुटन से नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट उपक्रम है सीएए। इसको लेकर भी गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्र की एकता को विखंडित करने के प्रयास हो रहे हैं। सीएए को लेकर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की साजिश हुई है और चुनावी माहौल में यह और तीव्रता से होने की संभावना है। राजनीतिक लोग सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना–देना नहीं, उसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया या फिर से उतारने के स्वर गूंजने लगे हैं। एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को गुमराह किया गया है, यह साजिश जिस किसी ने भी रची हो, लोगों और खासकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम अनेक विपक्षी दलों ने किया। इनमें कांग्रेस सरीखे वे दल भी थे, जो एक समय इस कानून में वैसे ही संशोधन करने की मांग कर रहे थे, जैसे किए गए। राजनीतिक दलों के साथ–साथ तथाकथित सेक्युलर तत्वों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी यह भ्रम फैलाया कि सीएए कुछ लोगों की नागरिकता छीनने का काम कर सकता है, जबकि यह कानून तो नागरिकता देने के लिए है। सीएए का विरोध करने वाले राजनेताओं एवं उनके उकसाये लोगों को देश से जैसे कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ अपना जनाधार चाहिए। वोट चाहिए। वोटों की संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीति के चलते राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को तार–तार किया जा रहा है? इन कानूनों में किसी के अहित की बात नहीं है, बल्कि जिनका अहित हुआ है, उनका हित निहित है, फिर क्यों बवाल है? पहले किसी भी गलत बात के लिए "विदेशी हाथ" का बहाना बना दिया जाता था।

राजनीतिक अस्तित्व में अतीत विशेषज्ञ

विनोद

डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीतिक मृत्युलेख कई बार लिखा गया है। सुपर ट्यूजडे रिपब्लिकन प्राइमरीज में उनका प्रभावशाली प्रदर्शन उन लोगों को मात देने का एक और उदाहरण है जिन्होंने उन्हें मात दी थी। जबकि ट्रम्प ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन हासिल नहीं किया है, सुपर मंगलवार प्राइमरी में उनकी लगभग जीत से संकेत मिलता है कि उनके अंतिम शेष जीओपी चौलेंजर निक्की हेली के लिए कोई और चुनावी रास्ता नहीं है। चूंकि ट्रम्प पहली बार 2015 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े थे, ऐसे कई क्षण आए हैं जो उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर सकते थे, जिनमें शामिल हैं। 2016 में एक्सेस हॉलीवुड टेप की रिलीज जिसमें वह महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में डींगें मारते दिखाई दिएय 2015 में युद्ध नायक जॉन मैक्केन और मारे गए अमेरिकी सैनिकों और विकलांग दिग्गजों के परिवारों के प्रति उनकी शत्रुताय 2017 में चार्लोट्सविले यूनाइट द राइट रैली के बाद उनकी टिप्पणियाँ जब उन्होंने कहा कि श्वेत वर्चस्ववादियों के एक समूह के बीच ष्बहुत अच्छे लोगष थेय सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस में बाधा डालने के लिए 2019 में उनका पहला महाभियोगय उनके पद पर रहते हुए कोविड महामारी से निपटने में, जिसमें 400,000 अमेरिकियों की मौत हो गईय और जो बिडेन के हाथों उनकी 2020 की चुनावी हार, जिसके कारण, विशेष रूप से, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने 6 जनवरी के कैपिटल विद्रोह को उकसाया – और उनका दूसरा महाभियोग चला। कई पर्यवेक्षकों ने सोचा कि ट्रम्प का राजनीतिक करियर 6 जनवरी, 2021 के बाद खत्म हो जाएगा। यह रिपब्लिकन अभिजात वर्ग के लिए विशेष रूप से सच था, जिन्होंने ट्रम्प के पद पर रहते हुए सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की थी, लेकिन निजी तौर पर सार्वजनिक जीवन से उनके प्रस्थान के लिए उत्सुक थे। यहां तक कि पिछली शताब्दी के सबसे चतुर कांग्रेसी नेताओं में से एक, सीनेट के बहुमत नेता मिच मैककोनेल भी यह अनुमान नहीं लगा सके कि ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी पर लगभग एक दशक तक मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे। दरअसल, मैककोनेल और अन्य रिपब्लिकन ने 2021 के विद्रोह के बाद ट्रम्प की आलोचना की, लेकिन अंततः 6 जनवरी को उनके आचरण पर दूसरे महाभियोग परीक्षण में उन्हें दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करने का फैसला किया। कारणरू उन्होंने माना कि ट्रम्प का राजनीति से प्रस्थान एक पूर्व निष्कर्ष था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपब्लिकन ने निष्कर्ष निकाला है कि उन्हें दोषी ठहराने के लिए वोट न केवल निरर्थक होगा क्योंकि ट्रम्प के प्रमुखता में लौटने की कभी उम्मीद नहीं थी, बल्कि इससे उनके अपने राजनीतिक करियर को भी अनावश्यक नुकसान होगा। ट्रम्प जीओपी नामांकन फिर से क्यों जीत रहे हैं? 2021 में व्हाइट हाउस से ट्रम्प की विदाई और कार्यालय से बाहर का समय उनके विरोधियों के लिए उनकी राजनीतिक संभावनाओं के लिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का एक और अवसर लेकर आया। उदाहरण के लिए, 2022 के मध्यावधि चुनावों में उन्होंने जिन रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन किया उनमें से कई ने खराब प्रदर्शन किया, जो आधुनिक इतिहास में जीओपी के सबसे खराब मध्यावधि प्रदर्शनों में से एक में योगदान देता है। इससे कई रिपब्लिकन और रूढ़िवादी अभिजात वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्रम्प के प्रति किसी भी नैतिक आपत्ति के बावजूद, वह एक चुनावी हारे हुए व्यक्ति थे, जो परित्याग के योग्य थे। कई रूढ़िवादियों ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को पूर्व राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी माना। अन्य लोग रिपब्लिकन पार्टी के अगले चेहरे के रूप में दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट या संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत और गवर्नर हेली की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अंततः इनमें से कोई भी संभावित उत्तराधिकारी पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन के करीब भी नहीं पहुंच सका। सुपर ट्यूजडे पर हेली का निराशाजनक प्रदर्शन इसका एक और स्पष्ट प्रमाण है। स्पष्ट रूप से, 2024 में ट्रम्प के लगभग सभी जीओपी प्रतिद्वंद्वियों ने – किसी न किसी बिंदु पर – उनका गर्मजोशी से समर्थन किया है।

जिस तरह से हम भोजन उगाते हैं उस पर पुनर्विचार करें

आदित्य

जब आप अमीर यूरोपीय किसानों और भारत में उनके गरीब समकक्षों की तस्वीरें देखते हैं, जो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध करने के लिए ट्रैक्टरों पर सवार होते हैं, तो दुनिया की कृषि प्रणाली में कुछ बुनियादी रूप से टूट जाती है। तथ्य यह है कि ये किसान जलवायु जोखिमों और नुकसान के युग में कृषि उत्पादन की बढ़ती लागत की गंभीर समस्या से महाद्वीपों में जुड़े हुए हैं। यूरोप में, विडंबना यह है कि फ्लैशप्वाइंट जलवायु विनियमन की शुरूआत थी, जिसके तहत खेतों को कीटनाशकों का उपयोग आधा करना होगाय उर्वरक उपयोग में 20 प्रतिशत की कटौतीय दोगुना जैविक उत्पादनय और जैव विविधता संरक्षण के लिए गैर–कृषि उपयोग के लिए अधिक भूमि छोड़ें। इसके अलावा, नीदरलैंड ने नाइट्रोजन प्रदूषण में कटौती करने के लिए अपने पशुधन की संख्या कम करने का प्रस्ताव दिया था और जर्मनी ने डीजल, एक जीवाश्म ईंधन पर अपनी सब्सिडी कम करने का प्रस्ताव दिया था। जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व संबंधी खतरे का सामना कर रही दुनिया में यह सब स्पष्ट रूप से आवश्यक है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, यूरोपीय संघ (ईयू) में कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती है – जो इसके वार्षिक उत्सर्जन का दसवां हिस्सा है। यदि अमीर किसानों के लिए राहत की यह लागत अधिक है, तो इससे हमारी दुनिया में उन किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो अस्तित्व के हाशिये पर हैं? ।कअमतजपेमउमदज तथ्य यह है कि यूरोपीय कृषि प्रणाली, जो आधुनिक कृषि का प्रतीक है, जैसा कि हम आज जानते हैं, भारी सब्सिडी के कारण बची हुई है। 1962 से, यूरोपीय संघ की सामान्य कृषि नीति (सीएपी) ने कृषि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है – बहुत आलोचना के बाद, समर्थन में कमी की गई लेकिन केवल मामूली रूप से। आज यह यूरोपीय संघ के बजट का लगभग 40 प्रतिशत है और इसमें किसानों को सीधे भुगतान शामिल है। यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक किसान को 2021 में प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में रू6,700 सालाना (लगभग 50,000 रुपये/माह) प्राप्त हुआ। इसके अलावा, कृषि को सुविधाजनक बनाने के लिए और अधिक निवेश किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, खेती की ष्प्रकृतिष विकसित हुई हैय खेत बड़े और अधिक समेकित हो गए हैं। छोटे कृषक अब बढ़ती इनपुट लागत, उच्च मानकों और नौकरशाही के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लागत बढ़ने के कारण बड़े खेतों को भी उच्च ऋण का सामना करना पड़ता है। जैविक खेती की प्रथा – आज यूरोपीय संघ की 10 प्रतिशत भूमि इस प्रणाली के अंतर्गत है – खेती की लागत बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। खेती अधिक सघन हो गई है – प्रति फसल या पशुधन अधिक उत्पादकता – और इसका मतलब है रसायनों और इनपुट का अधिक उपयोग, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ मिलकर और भी अधिक लागत का परिणाम देता है। लागत के इस सर्पिल को दो वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है – एक, भोजन की उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता और दो, जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के कारण बढ़ती फसल क्षति। यह गहन कृषि की प्रणाली है जिसे दुनिया में सराहा जाता है – यह कहा जाता है कि पर्यावरण मानकों को प्रणाली में बनाया जा सकता है और फिर भी किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं और व्यवसाय चला सकते हैं। जाहिर है इस मामले में ऐसा नहीं है। पश्चिमी दुनिया के देशों में भी भोजन की कीमत सस्ती नहीं है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं है. भारत में, दिल्ली के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी उपज के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) चाहते हैं। उन्हें समृद्ध यूरोप में अपने समकक्षों के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खाद्य खेती का समर्थन करने के लिए भारी सब्सिडी के बिना। तब उन्हें गंभीर हमले का सामना करना पड़ता है – सरकार को वितरण के लिए भोजन खरीदना होता है और इसलिए उसे कीमत को नियंत्रण में रखना होगाय उपभोक्ता (हम सभी) खाद्य मुद्रास्फीति की मार झेलना नहीं चाहते। इसलिए, भले ही किसान मौसम और कीटों के हमलों के कारण लागत और बढ़े हुए जोखिम के रूप में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हर बार खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और उन्हें लाभ हो सकता है, विकल्प सस्ते

आयात के माध्यम से कीमतों को कम करना है। वो हार। फिर वे मिट्टी, पानी या जैव विविधता के सुधार में निवेश नहीं कर सकते। इस प्रणाली में, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता पर्यावरण सुरक्षा उपायों की लागत में छूट देना है। अब उनसे कहा जा रहा है कि मुनाफे में बने रहने के लिए उन्हें उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है।

लेकिन महंगे इनपुट के कारण इसकी लागत अधिक होती है – इस खाद्य अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उच्च लागत का भुगतान उस देश में नहीं किया जाएगा जिसे किफायती भोजन की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार यूरोप के पैमाने पर व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकती है। यह भी स्पष्ट है कि गहन कृषि की इस प्रणाली में इतनी भारी वित्तीय सहायता भी पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि खेती की लागत कैसे कम की जाए और फिर भी किसानों के लिए पैसा कैसे रखा जाए। यहीं पर पुनर्योजी या प्राकृतिक खेती एक भूमिका निभाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर और इसे समर्थन देने के लिए महान नीति और विचारशील अभ्यास और विज्ञान के साथ। हमें स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए खाद्य खरीद नीतियों की भी आवश्यकता है, ताकि किसानों को अच्छे भोजन के लिए सुनिश्चित बाजार मिल सके।

अधिनायकवाद और स्वतंत्रता की, दुनिया आज के भारत के बारे में क्या कह रही

ललित

हाल ही में ध्रुव राठी नाम के एक युवक का एक लोकप्रिय वीडियो आया था, जिससे सरकार के समर्थक नाराज हो गए। इसके व्यापक तर्क को शीर्षक से समझा जा सकता है, जो था ष्क्या भारत तानाशाही बन रहा है? वीडियो में इस्तेमाल किए गए उदाहरणों में भाजपा द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पैनल में धांधली, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आदि शामिल हैं। शब्दकोश में तानाशाही को सरकार का एक रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति होती है और ष्सरकार का एक रूप जिसमें पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या एक छोटे समूह में केंद्रित होती हैष के रूप में परिभाषित किया गया है। मैं इसे पाठकों पर छोड़ दूँगा कि क्या ये परिभाषाएँ आज भारत में हमारे चारों ओर जो हो रहा है उससे मेल खाती हैं। तानाशाह शब्द, फासीवादी शब्द की तरह, अत्यधिक उपयोग किया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ खो सकता है क्योंकि इसे परिभाषा के बजाय दुरुपयोग के शब्द के रूप में देखा जाता है। जब सामाजिक वैज्ञानिक आशीष नंदी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री से मुलाकात का वर्णन किया, तो उन्होंने निम्नलिखित लिखारू "यह एक लंबा, मनोरंजक साक्षात्कार था, लेकिन इससे मुझे कोई संदेह नहीं हुआ कि यह एक फासीवादी का एक क्लासिक, नैदानिक मामला था। मैं कभी भी श्फासीवादीश शब्द का प्रयोग दुर्व्यवहार के रूप में नहीं करताय मेरे लिए यह एक निदान श्रेणी है जिसमें न केवल किसी की वैचारिक स्थिति बल्कि विचारधारा को प्रासंगिक बनाने वाले व्यक्तित्व लक्षण और प्रेरक पैटर्न भी शामिल हैं। नंदी ने कहारू "मोदी, मुझे पाठकों को यह बताते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि मोदी वस्तुतः उन सभी मानदंडों पर खरे उतरे हैं जो मनोचिकित्सकों, मनोविश्लेषकों और मनोवैज्ञानिकों ने सत्तावादी व्यक्तित्व पर वर्षों के अनुभवजन्य काम के बाद स्थापित किए थे। उनमें शुद्धतावादी कठोरता, भावनात्मक जीवन की संकीर्णता, प्रक्षेपण के अहंकार की रक्षा का व्यापक उपयोग, इनकार और हिंसा की कल्पनाओं के साथ अपने स्वयं के जुनून का डर का समान मिश्रण था – सभी स्पष्ट पागल और जुनूनी व्यक्तित्व लक्षणों के मैट्रिक्स के भीतर सेट थे। मुझे अब भी वह शांत, नपा–तुला लहजा याद है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ लौकिक साजिश के सिद्धांत को विस्तार से बताया था, जिसने हर मुसलमान को एक संदिग्ध गद्दार और संभावित आतंकवादी के रूप में चित्रित किया था। मैं साक्षात्कार से स्तब्ध होकर बाहर आया३" तानाशाही की ओर लौटने के लिए, मेरे विचार से एक कम भावनात्मक और अधिक विश्वसनीय प्रश्न यह पूछना है कि क्या हम सत्तावादी शासन के अधीन हैं। इसे ष्दूसरों की इच्छाओं या राय के प्रति चिंता की कमीष के रूप में परिभाषित किया गया है। अब, आइए यह देखने के लिए कुछ संकेतक देखें कि क्या यह मामला है। क्या रहे हैं? पहला, क्या सरकार के अंदर के लोगों की इच्छाओं और राय की कोई चिंता है? इसका उत्तर देने के लिए, आइए दो महत्वपूर्ण मामलों पर नजर डालें जहां हमारे पास निर्णायक सबूत हैं। पहला 24 मार्च, 2020 का राष्ट्रीय लॉकडाउन है। बीबीसी ने लॉकडाउन के एक साल बाद 240 आरटीआई (सूचना का अधिकार अनुरोध) दायर की, यह पूछने के लिए कि मोदी सरकार में कौन जानता था कि उस शाम लॉकडाउन की घोषणा की जा रही थी। क्या आपदा प्रबंधन से परामर्श लिया गया? या वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? सरकार की ओर से उत्तर थारू ष्नहींष। किसी से परामर्श या सूचना नहीं दी गई। दूसरा है नोटबंदी. 8 नवंबर, 2016 को कैबिनेट को बुलाया गया और मंत्रियों को अपने मोबाइल फोन नहीं लाने के लिए कहा गया, जिसका मतलब है कि उन्हें तब तक पता नहीं था जब तक कि पीएम ने उन्हें नहीं बताया कि उस शाम के बाद 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोट बेकार हो जाएंगे। चूँकि मंत्रियों को पता नहीं था, मंत्रालयों को पता नहीं था और उन्होंने इनमें से किसी भी घटना के लिए तैयारी नहीं की। सरकार के संसदीय स्वरूप सामूहिक जिम्मेदारी नामक चीज पर कार्य करते हैं। लेकिन नये भारत में नहीं. भारत में, राज्य के प्रमुख को नई संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि प्रधान मंत्री अध्यक्षता करना चाहते हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य का प्रमुख अनुपस्थित होना चाहिए। इसी तरह, और इसी कारण से, राज्य के प्रमुख को उस मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए नहीं कहा जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करना चाहते हैं। इस पर सवाल नहीं उठाया जाता, विरोध तो बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि यह विचार कि केवल एक व्यक्ति ही राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, यहां स्वीकार कर लिया गया है। हर जगह उसकी तस्वीर देखिएय कोई इससे बच नहीं सकता. प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो का दुरुपयोग करके इस सरकार ने विपक्ष के साथ क्या किया है और क्या कर रही है, इस पर हमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उस पर रोजाना अपडेट होता है. यह कोई मामला नहीं है कि संवैधानिक विपक्ष की ष्इच्छाओं और रायष के लिए कोई चिंता है। नागरिक समाज में जो लोग असहमत हैं, उन्होंने यह भी देखा है कि उन्हें सीधे जेल जाना होगा क्योंकि वे जो कहते हैं उसे सहन करने का कोई सवाल ही नहीं है। अंत में, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय पर बाहरी दुनिया भारत के बारे में क्या कह रही है। इस महीने, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय से वार्षिक वी–डेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है "भारत की निरंकुशता प्रक्रिया को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, पत्रकारों का उत्पीड़न शामिल है। सरकार की आलोचना, साथ ही नागरिक समाज पर हमले और डराना–धमकाना च विपक्ष।" इसी तरह के निष्कर्ष फ्रीडम हाउस से आए हैं, जो भारत को ष्आंशिक रूप से स्वतंत्रष की श्रेणी में रखता हैय नागरिक समाज संगठनों का वैश्विक गठबंधन सिविकस, जो भारत को दमित मानता है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने भारत को ष्त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रष के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया में कहीं भी ऐसे कोई सूचकांक नहीं हैं, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्हें हम मित्र और सहयोगी मानते हैं, जो बताते हैं कि 2014 के बाद से भारतीय अधिक स्वतंत्र हो गए हैं और भारत कम सत्तावादी हो गया है। कोई वस्तुनिष्ठ बचाव नहीं है। प्रधान मंत्री के समर्थक, और मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे कई लोग हैं, इसके बजाय हमें यह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि उनका दैवीय अधिनायकवाद हमारे और हमारे देश के लिए इतना अच्छा है।

इंडियाज टेकेड- चिप्स फॉर विकसित भारत का लाइव पीयू के विद्यार्थियों ने देखा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को श्इंडियाज टेकेडरू चिप्स फॉर विकसित भारतश के सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रो राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) संस्थान के आर्यभट्ट सभागार में किया गया।

प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत अंतर्गत करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमी कंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास बुधवार को किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये सुविधाएं गुजरात के धोलेरा, साणंद और असम के मोरीगांव में स्थापित की जाएंगी। इसका सजीव प्रसारण वीर बहादुर को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। यह परियोजना धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ौज) सुविधा और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ौज) सुविधा के लिए आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन सुविधाओं के जरिए सेमीकंडक्टर इको–सिस्टम दृढ़ होगा और भारत में इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ये यूनिट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हजारों युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो वंदना सिंह, कुलसचिव महेंद्र कुमार, वित्त अधिकारी संजय राय, निदेशक प्रो प्रमोद कुमार यादव, प्रो देवराज सिंह, प्रो मिथिलेश सिंह, प्रो गिरिधर मिश्र, डा प्रमोद कुमार, डा नीरज अवस्थी, डा धीरेंद्र चौधरी सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

स्थानीय उत्पाद से रोजगार सृजन सम्भव - कृपाशंकर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही रोजगार का अधिकतम सृजन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हर हाथ को रोजगार का स्वप्न तभी साकार रूप लेगा। यह बातें पूर्व गृहराज्य मंत्री और जौनपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने मंगलवार को कही। वह यहां जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्थापित स्टाल के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। इस स्टाल पर जौनपुर जनपद में हो रहे अचार मसाला व अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रहे उद्भव इंटरप्राइजेज ने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया है। श्री सिंह ने स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा यह कदम देश को दूरगामी परिणाम देगा। रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय स्वदेशी उत्पादकों को बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह योजना शुरू की गई है। उत्तर रेलवे मंडल के विभिन्न स्टेशनों लोकल उत्पादों की बिक्री हेतु आउटलेट, स्टॉल, क्योस्क का आवंटन संबंधित रेलवे स्टेशन पर किया गया है । श्एक स्टेशन एक उत्पादश योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्टॉल पर संबंधित स्टेशन के लोकल उत्पाद जैसे हस्तशिल्प कलाकृतियां, निर्माण व कपड़ा संबंधित उत्पाद, बन्देभारत ट्रेन के जौनपुर स्टापेज करने की मांग की

हैंडीक्राफ्ट व खाद्य उत्पाद इन स्टॉल्स पर उपलब्ध कराए गए है।

भाजपा नेता व लोकसभा प्रत्याशी श्री सिंह ने उद्घाटन स्थल से ही रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को सराहनीय बताते हुए आज चली लखनऊ पटना जिसके संदर्भ में रेलमंत्री द्वारा अतिशीघ्र उक्त मांग को पूरा करने के साथ ही मऊ से लोकमान्य तिलक को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन जल्द ही संचालित करने का आश्वासन दिया गया ।इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश सिंह उद्भव इंटरप्राइजेज के संचालक आशीष श्रीवास्तव आरक्षण प्रभारी अनुराग तिवारी रवि तिवारी, राहुल यादव स्टेशन अधीक्षक वी के सिंह आदि लोग मौजूद थे।

सांसद ने मेडिकल कालेज को दिया एम्बुलेंस

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धीकपुर को नया एम्बुलेंस सांसद ने दिया है ,और उसका पिता काटकर एंबुलेंस का शुभारंभ किया। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं में अन्य संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। एमबीबीएस छात्रों से वार्ता कर पठन–पाठन में जानकारी ली। लोकसभा सदर के सांसद श्याम सिंह यादव ने उमानाथ सिंह स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज मे मरीजो की उपचार सेवा के लिए एक एंबुलेंस उपलब्ध कराया ।जो आधुनिक संसाधनों से लैस है। जिससे मरीज को आने–जाने में बेहतर सुविधा होगी। सोमवार के अपराह्न एंबुलेंस सेवा का सांसद श्याम सिह यादव ने फीता काटकर उद्घाघाटन एवं शुभारंभ किया। इस अवसर उन्होंने कहा कि लोगों के बेहतर उपचार के साथ–साथ एमबीबीएस छात्राओं को पठान–पाठन की व्यवस्था अच्छी हो , जो बच्चे डॉक्टर बनकर यहां से निकले वह देश के कोने–कोने में जाकर लोगों की उपचार सेवा करें। और क्षेत्र का कॉलेज का नाम रोशन करें। इस दौरान वह बच्चों से भी रूबरू होकर उनके पठन–पाठन के बारे में जानकारी ली , उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी और स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन की मूलभूत आवश्यकता होगी वह दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ शिवकुमार, सीएमएस ए जाफरी,उप प्राचार्य रुचिरा सेठी, डा भारती यादव, चंद्रभूषण यादव, डॉ आशीष यादव, डॉ शशी पांडेय , लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ सीबीएस पटेल एवं वित्त नियंत्रक अतुल चौधरी मौजूद रहे।

पुलिस आवास निगम द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को उ0प्र0 पुलिस शिक्षा समिति के पक्ष में प्रदान किया गया चेक

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र को आज दिनांकः 12.03.2024 को पुलिस आवास निगम के अपर पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री प्रकाश डी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी के अंतर्गत पुलिस मॉडर्न स्कूल हेतु सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति, लखनऊ के पक्ष में 17,58,000/– (सत्रह लाख अट्ठावन हजार) रूपये का चेक प्रदान किया गया। निगमीय सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निगम प्रत्येक वर्ष अर्जित किये गये लाभ से उ०प्र० पुलिस शिक्षा कोष को नियमित रूप से धनराशि प्रदान करता रहा है। इस दौरान उ०प्र० पुलिस आवास निगम के महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) संजीव सक्सेना मौजूद रहे।

थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अदद मोटर साइकिल बरामद

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस के मुताबिक आज दिनांक–12.03.2024 को थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा 02 अदद मोटर साइकिल बरामद करते हुए 04 नफर वाहन चोर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण बताते हुए थाना पुलिस ने कहा कि आज दिनांक 12.03.2024 को थाना मड़ियाँव पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित वारंटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में जीएसआई पावर हाउस चौराहे के पास मौजूद थी कि जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि चार अज्ञात व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिल से किसी अप्रिय घटना को अन्जाम देने के उद्देश से सेक्टर क्यू चौराहे के पास बने सार्वजनिक शौचालय के पास 2 मोटरसाइकिल के साथ खड़े है इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले मुखबिर को साथ लेकर सेक्टर क्यू चौराहे से कुछ दूर पर ही आकर खड़े हो गये और तभी मुखबिर खास द्वारा दूर 2 मोटरसाइकिल के साथ खड़े चार अज्ञात व्यक्तियो कि ओर इंशारा कर के बताया की साहब ये वही व्यक्ति खड़े है जो किसी गंभीर घटना करने के फिराक में है तब हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताये गये संदिग्ध व्यक्तियो के ओर आगे बढे तो पुलिस वालो को सामने आता देख चारो संदिग्ध व्यक्तियो ने भागने का प्रयास किया तभी हम पुलिस वालो द्वारा सिखलाये गये तरीके से एक बारगी दबिश दे कर घेरकर चारो संदिग्ध व्यक्तियो को दो मोटरसाइकिल से साथ पकड़ लिया पकड़े गये पहले व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मो० अरजू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी–मड़ियाव गाँव थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र–22 वर्ष बताया, दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संदीप पुत्र राम प्रसाद निवासी–छोटा पंहाडपुर सेक्टर जे थाना थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष बताया, तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अकीबुल पुत्र कुद्दूश निवासी–मूल पता–ग्राम खूरा बारी सरेली बरपटा रोड़ थाना बरपटा जनपद– गुहाटी असम हालपता पुरनिया पुल के पास झापड़ी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष बताया तथा चौथे व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए जामा तलीशी ली गयी तो उसने अपना नाम आकाश पुत्र राजेश निवासी–मूल पता ग्राम – वेहटा मुर्तजा बक्श थाना बघौली जनपद हरदोई हाल पता – मुबारपुर थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र–25 बर्ष बताया चारो संदिग्ध व्यक्तियो के पास दो मोटरसाइकिल जिसका विवरण निम्न है– 1– हिरोहोण्डा स्पलेडर काले रंग जिसका नम्बर UP32DK1057 चेसिस नम्बर –MBLHA10ADA9K00626, इंजन नम्बर– HA10 EHA9K00712]2–हिरो स्पलेडर प्लस काला रंग बिना नम्बर प्लेट है जिसका चेचिस नम्बर– MBLHAW117LHK82802 इंजन नम्बर– HA11 EVLHKC2697 अंकित है जिसके सम्बन्ध में मोबाइल चालन ऐप से जानकरी करने पर पता चला की गाडी नम्बर UP32LS6252 है की बरामद हुयी। चारो सन्दिग्ध व्यक्तियो से पास दोनो मोटर साइकिलो के सम्बन्ध में पूछा गया तो घबरा कर चुप हो गये कड़ाई से पूछने पर बताया की साहब यह दोनो मोटरसाइकिल हम चारो लोगो ने अलग–अलग जगह से चोरी की थी स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि एक मोटरसाइकिल जानकीपुरम व एक मोटर साइकिल फैजुल्लागंज से चुराया था जिसे हम चारो लोग बेचने के फिराक में आज घूम रहे थे तभी आप लोगो ने हमे पकड़ लिया हम लोग मोटर साइकिल चोरी कर राह चलते लोगो को औने पौने दाम पर बेच देते है उससे जो पैसा मिलता है उसे हम लोग नशा और शौक करने में खर्च कर देते चारो अभियुक्तगणो को मोटरसाइकिल चोरी करने के जुर्म से अवगत कराते हुएगिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशो निर्देशो का पूर्णतय पालन किया गया। बरामदगी के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभिगण उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है। जिनके आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आलोक कुमार चौधरी,उप निरीक्षक अकबर अली, हेड कांस्टेबल मिथलेश गिरी, कांस्टेबल ओम प्रकाश थाना मड़ियांव लखनऊ शामिल रहे।

एयरटेल ने लखनऊ में सभी कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ व्यावहारिक संपर्क के लिए फ्रंटलाइन टीमों में शामिल करके ग्राहक दिवस मनाया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारत के प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक, भारती एयरटेल ("एयरटेल") ने आज देश में अपने सभी कार्यालय स्थानों पर ग्राहक दिवस मनाया। ऐसे सभी एयरटेल कर्मचारी, जो सीधे ग्राहकों से संपर्क बनाए रहते हुए काम करने की जिम्मेदारियों में नहीं थे, वे अपनी रोजमर्रा की भूमिकाओं से बाहर निकलकर ग्राहकों के सीधे बातचीत करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों में शामिल हुए। देश के सभी एयरटेल कार्यालय स्थानों के कर्मचारियों ने बाजारों में होम डिलीवरी इंजीनियरों, फाइबर एक्सक्यूटिव्स और रिटेल कर्मचारियों के साथ काम किया। इन कर्मचारियों में शीर्ष सीनियर लीडरशिप टीम से लेकर सभी कार्यालयों के जूनियर मैनेजर तक सभी शामिल रहे।

ग्राहक दिवस, एयरटेल की कई पहलों का एक हिस्सा है, जो ग्राहकों को सबसे अधिक महत्व देने के एयरटेल के सिद्धांत पर केंद्रित हैं। अपने सभी कर्मचारियों को ग्राहकों से प्रत्यक्ष मिलने–जुलने का अवसर देकर, एयरटेल का लक्ष्य ग्राहकों के दृष्टिकोण और ग्राहकों की जरूरतों खासकर उनकी चिंताओं और सुझावों को समझकर उनका कंपनी के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। कंपनी को विश्वास है कि "ग्राहक दिवस" हमारी कंपनी में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को "देखने–समझने का नया नजरिया" देगा और पूरे संगठन में ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए काम करने की लगन जगाने के लिए नई मानसिकता और संस्कृति को उजागर करेगा।

मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में भारतीय जन मानस को एकजुट करना है - प्रो डी डी दुबे पूर्व कुलपति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। तानाशाही के विरुद्ध भारत विषय प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। जिसमे जिले के तमाम समाजसेवी, प्रमुख शिक्षाविद, कानूनविद, अधिवक्ता, सैनिक बुद्धिजीवी, कर्मचारी व पत्रकार उपस्थित हुए। वार्ता में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डीडी दुबे ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही के विरोध में भारतीय जनमानस को एकजुट करना है इसी संदर्भ में यह बैठक का आयोजन किया गया है।

डॉ. अनुराग मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान व आजादी बचाओ जन आंदोलन को देश के प्रमुख शिक्षाविद, कानूनविद, अधिवक्ता, सैनिक बुद्धिजीवी, कर्मचारी, छात्र और नौजवान साथियों को मिलाकर एक जागरूक जनमंच तैयार किया जा रहा है और यह प्लेटफॉर्म ष्तानाशाही के विरुद्ध भारतष की सोच रखने वालों को साथ लेकर लोकतंत्र, संविधान व आजादी बचाओ जन–आंदोलन चलाने जा रहा है ।

जयप्रकाश सिंह कामरेड ने कहा कि जन आंदोलन का एक पर्चा आज जारी किया जा रहा है, जिसे जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा जिला मुख्यालय की प्रमुख चौराहों तथा ग्रामीण अंचल के बाजारों व गांवों में जागरूक जनमंच नुक्कड़ सभाएं करेगा तथा पर्चे वितरित करेगा और लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का कार्य करेगा।

जन आंदोलन की औपचारिक घोषणा आज प्रेस वार्ता के जरिए

की गई जिसमें प्रमुख रुप से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर धरणीधर दुबे, सेवानिवृत सैन्य अधिकारी मेजर सभाजीत दुबे, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश कामरेड, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री आनंद मिश्र एडवोकेट, विवेक रंजन यादव ष्बबलूष प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, समाजसेवी विजय सिंह बागी, डॉ. जीएस त्रिपाठी, श्री नेयाज ताहिर शेखू एडवोकेट,पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस , शौकत अली ष्मुन्ना राजाष सद्र मरकजी शीरत कमेटी जौनपुर, मनीष देव ष्मंगलष्सभासद उर्दू बाजार,निसार अहमद जी, समाजसेवी प्रदीप मिश्र, पूर्वांचल प्रांत प्रभारी आम आदमी पार्टी जौनपुर, समाजसेवी व पत्रकार अतुल कुमार तिवारी, हफीज शाह पूर्व सद्र मरकजी शीरत कमेटी जौनपुर,जफर मसूद पूर्व सद्र मरकजी शीरत कमेटी,एच. एन. तिवारी समाजसेवी,डॉ विजय प्रताप तिवारी प्रदेश अध्यक्ष अनुदानित महाविद्यालयध् विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश,बबलू गुप्ता समाजसेवी,अनीता मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी,बंटी अग्रहरि समाजसेवी, हर्षवर्धन श्रीवास्तव अधिवक्ता ईत्यादि प्रमुख चेहरे इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं।

भाजपा की सरकार मे आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है - दयाशंकर मिश्र

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित लाभार्थीयो से सम्पर्क, एन०जी०ओ० के कार्यकर्ताओ के साथ बैठक प्रकोष्ठ के कार्यकम मे भाग लेने के उपरांत घर–घर जन सम्पर्क करने पहुँचे आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दायशंकर मिश्र दयालु ने होटल मे कोहोर्ट मिलन एंव विकसित भारत संकल्प पत्र की बैठक लिया अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने की। उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए अपना पल पल समर्पित किया है। एक घंटे की भी छुट्टी नही ली। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। शायद ही कोई घर परिवार होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नही हुआ होगा।भाजपा 2024 के लोकसभा मतदान में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगी। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का अटूट विश्वास है एवं प्रधानमंत्री ने भी जनता को विकास की गारंटी दी है जो की जनता के बीच विश्वास के भाव को दर्शाती है इसलिए हमारी देवतुल्य जनता अपना मन बना चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठाएगी। उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर, निर्धन के घर में मुफ्त राशन, स्वास्थ्य की सुविधा सहित अन्य कई योजनाएं जनहित में लागू की है और आम जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। उक्त अवसर

कार्यक्रम का संचालन जसविंदर सिंह ने किया।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आरक्षण प्रदान किया गया है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है आज नारी निडर होकर कहीं भी घूम सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर भारत और प्रदेश को विकास के क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। भाजपा शासन में नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। महिलाओं को पर गिरीश चंद्र यादव लोक सभा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह ब्रहदेव मिश्र हरिश्चंद्र सिंह सुशील मिश्र राजेश श्रीवास्तव सुभाष सिंह रामसूरत मौर्य धनंजय सिंह श्याममोहन अग्रवाल अमित श्रीवास्तव विकास शर्मा एस के सिंह विनोद सिंह तेज सिंह संतोष सिंह वत्स कीर्ति सिंह मनोज सिंह रविंद्र सिंह संतोष उपाध्याय यादवेन्द्र मिश्रा मनोज श्रीवास्तव हरिद्वारी विश्वकर्मा आमोद सिंह विनीत शुक्ला अरुण प्रजापति जामी हबीब खान विपिन द्विवेदी ओमप्रकाश सिंह नरेंद्र उपाध्याय अनिल गुप्ता सुशांत चौबे इंद्रसेन सिंह प्रतीक मिश्रा आवधेश सोनकर आदि उपस्थित रहे।

जनपद के शतप्रतिशत विद्यालयों को निपुण भारत की श्रेणी लाया जाये – जिलाधिकारी

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) आज गांधी भवन हाल में जिला बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत एआरपी द्वारा चयनित एवं शिक्षा संकुल विद्यालयें के कक्षा 1–3 में अध्यनरत विद्यार्थियों का डी0एल0एड0 प्रशिक्षओ द्वारा माह दिसम्बर 2023 में किये गये आकलन के आधार पर आयोजित सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया तथा निपुण हुए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकध्सहायक अध्यापक को निपुण विद्यालय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी जनपद में निपुण हुए कुल 192 विद्यालयों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हमे जनपद के विद्यालयों को निपुण भारत में सम्मान जनक स्थिति में लाने के लिए उपस्थित निपुण विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक अपने क्षेत्र के आस–पास के विद्यालयों को शिक्षकों से सम्पर्क करें और जैसे प्रयासों से अपने विद्यालय को निपुण बनाया है उन्हें भी बताये ताकि जनपद के शतप्रतिशत बेसिक विद्यालय निपुण भारत की श्रेणी में लाया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि निपुण विद्यालय बनाने के लिए बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थित करने के साथ सभी के साथ समान व्यवहार करें और शिक्षा में कमजोर बच्चों को अतिरिक्त क्लास देकर निपुण बनायें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उस्थित शिक्षक–शिक्षकाओं मतदान की शपथ दिलायी तथा कहा कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन में जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें एवं अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी ने कहा कि निपुण विद्यालय बनाने के लिए शिक्षक एवं समस्त स्टाप समन्वय एवं रणनीति बनाकर कार्य करें और बच्चों की रूचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। उन्होने कहा कि कायाकल्प में विद्यालयों ने अच्छा कार्य किया है पर निपुण भारत मिशन में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने एवं अन्य विद्यालयों को शतप्रतिशत निपुण बनाने में सहयोग करें। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिये कि शीर्घ ही जनपद के अधिक से अधिक बेसिक विद्यालयों को निपुण भारत की श्रेणी में लाया जायेगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, सभी खण्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि उस्थित रहें।

हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम बी ई ओ टड़ियावां अनुज कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) ब्लाक संसाधन केंद्र टड़ियावां पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी टड़ियावां अनुज कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ,जिसकी औपचारिक शुरुआत मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी महोदय सुशील कुमार मिश्र के द्वारा सरस्वती पूजन

व दीप प्रज्वलित कर किया गया।इसके साथ ही आए अन्य अतिथिगण तहसीलदार सदर श्री विनीत कुमार सिंह, नायाब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी टड़ियावां श्री नरोत्तम कुमार, सीडीपीओ श्रीमती कुमुद मिश्रा ,ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व समाजसेवी अनुज गुप्ता, ग्राम प्रधान टड़ियावां अमित गुप्ता ,एआरपी विवेक गुप्ता,बीना वर्मा,रूचि शुक्ला ने भी सरस्वती पूजन किया।इसके बाद बीईओ टड़ियावां द्वारा आए सभी अतिथियों का बैज अलंकरण व माल्यार्पण कर स्वागत किया।उपजिलाधिकारी सदर,तहसीलदार सदर,नायाब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी टड़ियावां,ग्राम प्रधान परसनी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।उच्च प्राथमिक विद्यालय टड़ियावां के बच्चों द्वारा अतिथियों का स्वागत गीत से स्वागत किया गया।10 न्याय पंचायत के स्कूल रेडीनेस के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 शिक्षक संकुल को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया,इसके साथ ही 50 निपुण बच्चों को स्कूल बैग व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।निपुण विद्यालय पर एआरपी विवेक गुप्ता,कायाकल्प, स्कूल रेडीनेसध् वालवाटिका पर एआरपी बीना वर्मा,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एआरपी रूचि शुक्ला द्वारा विस्तार से जानकारी दी गयी।राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान क्विज में टाप 10 बच्चों को उपजिलाधिकारी हरदोई द्वारा प्रशस्तिपत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया साथ ही टाप 5 बच्चों को कैश प्राइज भी दिया गया,जिससे टाप 5 बच्चों को जिलास्तर पर होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में अपने माडल के साथ उपस्थित होने हेतु प्रेरित किया गया।एस डी एम सदर द्वारा बच्चों व शिक्षों से गुणवत्तापूर्णशिक्षा पर जोर देते हुएसभी बच्चों को निपुणकरने हेतु प्रेरितकिया गया।खंडविकास अधिकारी नरोत्तमकुमार द्वारा कायाकल्प में पूर्ण सहयोग करते हुए विद्यालय में हुए कार्य से अवगत कराया गया।इस अवसर पर सभी नोडल शिक्षक संकुल, नोडल शिक्षक, कोलोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकत्री ,नीलेश सिंह, मंजेश अवस्थी,अशोक राठौर, नितिन श्रीवास्तव, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष राघवेन्द्र पांडेय उपस्थित रहे।

सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है – प्रेमावती

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पीएम सूरज पोर्टल को लांच किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कुछ आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया गया। उन्होंने लाभार्थियों से योजनाओं के सम्बन्ध में उनके अनुभव जाने। लाभार्थियों ने योजना से उनके जीवन में आये बदलावों के बारे में बताया। नगर पालिका हरदोई के सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

दिखाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत योजनाएं चला रही है। योजनाओं से इन वर्गों की आर्थिक बेहतर हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। अतिथियों द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किये गए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये गए। इस अवसर पर एलडीएम अरविन्द रंजन, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

शालीमार गेटवे मॉल ने ग्राहकों के लिए पेश किया रोमांचक गेटवे टू शॉप एंड विन इवेंट

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राजधानी में शालीमार गेटवे मॉल खरीदारी करने वालों के लिए एक बेमिसाल जगह बन चुका है। ये मॉल सीधे मेट्रो और बस स्टैंड से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां आना–जाना बेहद आसान है। शालीमार गेटवे मॉल को 13 मार्च, 2024 से शुरू होने वाले ष्योर गेटवे टू शॉप एंड विनष इवेंट की घोषणा करते हुए बेहद रोमांचित है। ये शानदार शॉपिंग फेस्टिवल पूरे एक महीने तक चलेगा, जिसमें ग्राहकों के लिए ढेर सारे आकर्षक इनाम और सरप्राइज रखे गए हैं। शालीमार गेटवे मॉल आपके लिए खरीदारी का शानदार अनुभव लेकर आया है। अब आप न सिर्फ खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि हर हफ्ते लकी ड्रॉ में भाग लेकर ढेर सारे शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। मॉल के किसी भी स्टोर से सिर्फ घ500 से अधिक की खरीदारी करने पर आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। हर हफ्ते निकलने वाले लकी ड्रॉ में आप फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, कूलर, आयरन, फ्रायर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक स्टोव, हैंड ग्राइंडर, डिनर सेट और भी बहुत कुछ जीत सकते हैं। ग्राहकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, शालीमार गेटवे घ7500 या उससे अधिक खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मूवी मैक्स की तरफ से दो मुफ्त मूवी टिकट दिए जाएंगे। रू15,000 से ज्यादा खरीदारी करने पर एमआरपी रू6,250 का एक ट्रॉली बैग उपहार में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रू20,000 से अधिक खर्च करने पर एमआरपी रू7,150 का प्रीमियम ट्रॉली बैग जीता जा सकता है। यह खास ऑफर मार्च 2024 के पूरे महीने में सिर्फ सोमवार से गुरुवार तक ही मान्य है। यह स्टॉक समाप्त होने तक मान्य है और अन्य ऑफर के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस अवसर पर शालीमार गेटवे मॉल के सीनियर जनरल मैनेजर लीजिंग, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट श्री सुशील आहूजा ने कहा, ष्हम अपने ग्राहकों से मिल रहे निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हैं। इस इवेंट के माध्यम से, हम नए जोश के साथ खरीदारी के माहौल को और बेहतर बनाना चाहते हैं। सीधी कनेक्टिविटी मॉल को ग्राहकों के लिए सुलभ और पसंदीदा बनाती है।जो एप्पल, सैमसंग, वेस्टसाइड, लाइफस्टाइल, मैक्स और रिलायंस जैसे शीर्ष ब्रांड्स की तलाश में हैं। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यह ऑफर शालीमार गेटवे मॉल में आने वाले सभी लोगों के लिए यादगार पलों और सुखद आश्चर्यों का खजाना बन जाए। तो आइए, शालीमार गेटवे मॉल में एक महीने लंबे उत्सव में शामिल हों। रोमांचक उपहार, फायदेमंद खरीदारी का अनुभव पाने का मौका पाएं। यह समय मॉल में हर बार आना यादगार और फायदेमंद बनाने का यह शानदार अवसर है, इसे चूकें नहीं।

बच्चियां घर जाकर अपने माता पिता को मतदान का संकल्प अवश्य दिलाएं - एमपी सिंह'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' वेणी माधव विद्यापीठ बालिका इण्टर कॉलेज में बुधवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता पर आधारित निबंध व रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता विजेताओं को जिलाधिकारी ने पुरस्कार वितरित किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की बच्चियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चियां घर जाकर अपने माता पिता को मतदान का संकल्प अवश्य दिलाएं। मतदान प्रतिशत में शीर्ष जनपदों में शामिल होने के लिए जनपद के लोगों को शत प्रतिशत मतदान करना है। उन्होंने कहा कि जेन्डर अनुपात बढ़ा है। अब नारी शक्ति की जिम्मेदारी है कि मतदान अवश्य करें। उन्होंने बच्चियों को आयोग की ओर से जारी क्यूआर कोड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं। सी विजिल ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रहता है। ई केवाईसी के माध्यम से हम अपने उम्मीदवार के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में महिलाओं, दिव्यांगों व युवाओं को समर्पित बूथ बनाये गए हैं। वोट देना अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य भी है। उपनिदेशक कृषि डॉ नंदकिशोर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान आवश्यक है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि छात्राएं अपने घर परिवार व आस पास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने विद्यालय की छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलायी। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य व शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे।

बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल में कोर ड्रिलिंग कर रहे वैज्ञानिक

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। क्वाटरनरी लेक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (बीएसआईपी), लखनऊ ने क्वाटरनरी लेक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट (बीएसआईपी–क्यूएलडीपी) पर एक प्रमुख परियोजना शुरू की, जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थलाकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थलीय पर्यावरण के मानसून–संचालित जलवायु इतिहास का पुनर्निर्माण करना है। इस मेगा परियोजना के लिए देश के विभिन्न राज्यों से गहरे झील (सांम) तलछट (मकपउमदज) कोर

की आवश्यकता है। बीएसआईपी ने चयनित झील स्थलों से कोर ड्रिलिंग के लिए भारतीय भू–चुंबकत्व संस्थान (आईआईजी), मुंबई के साथ सहयोग किया है। संभावित ड्रिल स्थलों की पहचान के लिए ड्रिलिंग शुरू होने से पहले सीएसआईआर–राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद के विशेषज्ञों की टीम द्वारा भूभौतिकीय सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। हाल के दशकों में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (आईएसएम) घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और चरम घटनाओं में महत्वपूर्ण स्थानिक विविधता है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान आईएसएम की अवधि और तीव्रता में बदलाव आया है और यह अप्रत्याशित है, जिससे जबरदस्त कृषि और आर्थिक नुकसान हुआ है। भविष्य के जलवायु मॉडलिंग के लिए सटीक पुराजलवायु डेटा की आवश्यकता होती है, जो गंगा के मैदान (जीपी) और कोर मानसून जोन (सीएमजेड) से उत्पन्न किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल होंगे। ऐसे जलवायु अध्ययन के लिए, झीलें स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा संग्रह हैं। आसपास के वातावरण से एकत्रित तलछट में विभिन्न जैविक और अजैविक प्रॉक्सी का अध्ययन स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों, झील के पानी के रसायन विज्ञान, तापमान और झील की उत्पादकता का उच्च–विभेदन इतिहास प्रदान करता है। बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी. ठक्कर के नेतृत्व में बीएसआईपी के 23 वैज्ञानिकों की टीम उच्च–विभेदन वाले पुरा–जलवायु डेटा के लिए विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉक्सी के लिए तलछट कोर का अध्ययन करेगी। बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी. ठक्कर के नेतृत्व में डॉ. अनुपम शर्मा, डॉ. कमलेश कुमार, डॉ. नवाज अली, डॉ. मयंक शेखर, डॉ. अनुराग कुमार, अरविंद तिवारी, व नजाकत अली और आईआईजी के निदेशक प्रोफेसर ऐ पी डिमरी के नेतृत्व में डॉ. बी.वी लक्ष्मी, एवं डॉ. के. दीना दयालन वर्तमान में यूपी के बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल में कोर ड्रिलिंग कर रहें हैं। ड्रिलिंग टीम ने अब तक 10–मीटर गहरा कोर प्राप्त कर लिया है और अधिक गहराई तक ड्रिल करने की योजना बनाई जा रही है। यह पहली बार है कि बीएसआईपी, आईआईजी और एनजीआरआई के सहयोग से ऐसे गहरे कोर की ड्रिलिंग में शामिल है जो पिछले 50000 वर्षों से मध्य गंगा मैदान पर मानसूनी बदलावों को समझने में मदद करेगा।

क्यूएलडीपी के दूसरे चरण के दौरान, बीएसआईपी ड्रिलिंग कोर के लिए इस अध्ययन को हिमालय, राजस्थान और भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय हिस्से तक विस्तारित करेगा। बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी. ठक्कर ने यह भी कहा, "हम जलवायु–संस्कृति संपर्क का अध्ययन करने और सामाजिक प्रतिक्रिया को देखने और भारतीय उपमहाद्वीप के पुराजलवायु मॉडलिंग के लिए विशाल डेटा का उत्पादन करने में भी सक्षम होंगे, जो वैश्विक महत्वता प्रदान करेगा। यह परियोजना युवा शोधकर्ताओं (पीएचडी और पोस्ट–डॉक्स) को भी प्रशिक्षित करेगा जो इस तरह के अत्याधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों को अगले स्तर तक ले जाएंगे।

आरजेबी में हुए माक ड्रिल में समय रहते फायर कर्मी ने आग पर पाया काबू

अयोध्या। मंगलवार की शाम साढ़े दस बजे राम जन्मभूमि परिसर व आसपास क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों व अग्निशमन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों में कुछ समय हड़कंप मच गया जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर गर्भगृह के उत्तरी गेट के सम्मुख सीसीआर द्वारा आग लगने की सूचना वायरलेस सेट पर राम जन्मभूमि फायर स्टेशन पर गूंजने लगी।सूचना मिलते ही सीएफओ आर एस त्रिपाठी के निर्देश पर अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाइन नागेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ने त्वरित अग्निशमन प्रभारी राम जन्मभूमि परिसर गिरीश दूबे के साथ दमकल वाहन के साथ घटना स्थल पर पहुंचे।इन दोनों फायर अधिकारियों ने फायर कर्मियों की मदद से बिना समय गंवाए त्वरित आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलते ही वहां पर मौजूद एसपी सुरक्षा अशोक कुमार सिंह,सीओ परिसर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों व इन दोनों फायर विभाग के अधिकारियों ने उस समय राहत

की सांस लिया कि जब उन्हें पता चला कि यह एक महज माकड्रिल था।जो आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, एसएसपी राज करन नय्यर के निर्देश पर चलाया गया था। अग्निशमन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करने व आग पर काबू पाने पर पुलिस अधिकारियों ने इन दोनों फायर अधिकारियों व कर्मियों की पीठ थपथपाई। इस मौके पर एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा व यहां पर तैनात कर्मियों की सतर्कता को लेकर बीच बीच में इस तरह का अभियान चलता रहेगा।

राज्यकर्मचारी संयुक्त परिषद ने घोषित किया मतदाता जागरण अभियान का कार्यक्रम

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस आशय

की जानकारी आज लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दिया है। उन्होंने अवगत कराया है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक मतदान की आवश्यकता होती है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पूरा प्रयास है कि लोकसभा में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनपद शाखाओं को निर्देश भेजे जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री श्रीमती अरुणा शुक्ला ने बताया है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मंडल एवं जनपद स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर प्रेसवार्ता का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता अभियान की शुरुआत झांसी मंडल से हो रही है ,जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी 17 मार्च को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मंडल के कर्मचारियों के साथ बैठक कर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। जे एन तिवारी ने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विकास उन्मुख , स्थाई लोकहित में समर्पित, भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाने वाली , राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए शत प्रतिशत मतदान जरूरी है। मतदान एक राष्ट्रीय पर्व है ,इसमें हिस्सा लेना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यह ऐसा अवसर है जब हम लोकतंत्र की सार्थकता प्रमाणित करते हुए एक लोकप्रिय सरकार का गठन करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि संयुक्त परिषद के मंडल एवं जनपद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, समस्त मंडल आयुक्त एवं समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को संयुक्त परिषद द्वारा ईऋमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है। मंडल स्तर की प्रेस वार्ताओं में राज्य कर्मचारी परिषद संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे एवं महामंत्री श्रीमती अरुणा शुक्ला प्रतिभाग करेंगे।

आईआरपीएफएस प्रोबेशनर्स को अत्यधिक व्यावसायिकता और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया गया प्रोत्साहित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। कठोर संस्थागत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, 7 आईआरपीएफएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ में आयोजित की गई। रेलवे में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए परिवीक्षार्थियों को इनडोर और आउटडोर विषयों में 78 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। रमेश चंद्र, आईजी–सह–पीसीएससी, एमसीएफ, रायबरेली ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। प्रतिज्ञा लेने के बाद, 7 आईआरपीएफएस प्रोबेशनर रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य बन गए हैं।

डॉ. ए.एन. झा, डीआइजी–प्रशिक्षण, जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ ने अकादमी की प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रमेश चंद्र, आईजी–सह–पीसीएससी, एमसीएफ, रायबरेली ने पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए। रजत कुंडगीर, आईआर पीएफएस–प्रोबेशनर को आउटडोर विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आउटडोर सर्वश्रेष्ठ पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

अम्बु पी. कुमार, आईआर पीएफएस– प्रोबेशनर को इनडोर विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंडोर बेस्ट मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। उन्हें सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऑल राउंड बेस्ट मेडल और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया। अम्बु को स्वर्गीय श्री उदय शुक्ला, सर्वश्रेष्ठ प्रोबेशनर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया।

अपने संबोधन में, मुख्य अतिथि ने कठोर प्रशिक्षण के बाद आरपीएफ परिवार में आईआरपीएफएस प्रोबेशनर का स्वागत किया और उनसे आरपीएफ में राष्ट्र की सेवा के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी, युवा आईआरपीएफएस प्रोबेशनरों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें अत्यधिक व्यावसायिकता और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में, पीओपी के पूरा होने पर, सेंथिल के., सीनियर एससी ट्रेनिंग, जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या - 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।